

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

आदेश

दिनांक 25 जनवरी, 2008

संख्या 3943-र-3-2008/862.—चूंकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना संख्या 991-र-3-2007/3878, दिनांक 28 मार्च, 2007, में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् ग्राम गद्दी केसरी, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायिक काम्प्लेक्स तथा रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए अपेक्षित घोषित की गई है।

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलक्टर, सोनीपत को निर्देश देते हैं कि वह पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

धर्मवीर,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Order

The 25th January, 2008

No. 3943-R-3-2007/862.—Whereas, the land described in the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, Notification No. 991-R-3-2007/3878, dated the 28th March, 2007, issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for the construction of Judicial Complex and houses for Judicial Officers at Village Garhi Kesri, Tahsil Gannaur, District Sonapat.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Sonipat, to take order for the acquisition of the land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DHARAM VIR,

Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government Haryana,  
Revenue and Disaster Management Department.